ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344
RNI : UPBIL/2016/67980
VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking An Analisation

Peer Reviewed / Refereed Journal

Impact Factor
GIF = 0.543
Impact Factor
IIJIF = 6.134
Indexed with
Google scholar
Impact Factor
SJIF = 5.879

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	**लोकपाल सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य : एक अध्ययन** अंजना खेर, उज्जैन, म.प्र.	1-6
2	**ई गवर्नेंस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ** नागरत्ना गनवीर एवं आबेदा बेगम, राजनांदगांव	7-8
3	**भारतीय राजनीति के समक्ष साम्प्रदायिकता की चुनौती, कारण एवं समाधान** कल्लन सिंह मीना, गंगापुर सिटी, राजस्थान	9-13
4	**प्राचीन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में गणतन्त्रात्मक व्यवस्था का विकास** कविता देवी, मोर माजरा, करनाल	14-16
5	**नरेश मेहता के काव्य में भाव–बोध** शशि बाला रावत, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	17-18
6	**अनसुलझे सवालों से जूझता उपन्यास 'एक इंच मुस्कान'** मीना कुमारी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	19-21
7	**माधवी : स्त्री जीवन की त्रासदी** हबीब खान, डीडवाना, राजस्थान	22-25
8	**मोहन राकेश के नाटकों में पारिवारिक बिखराव** किरन लता दुबे, पश्चिम बंगाल	26-29
9	**'दस बरस का भँवर' उपन्यास में मनोविकृति स्किजोफ्रेनिया की अभिव्यक्ति** सुरिन्दर कौर, श्री मुक्तसर साहिब	30-33
10	**हिन्दी स्तंभ–लेखन की परंपरा और हरिशंकर परसाई** दीप नारायण चौहान, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	34-36
11	**प्रभा खेतान की कृतियों में 'स्त्री–विमर्श'** **(बाजार के बीचः बाजार के खिलाफ भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न के संदर्भ विशेष में)** रामयज्ञ मौर्य, मेरठ	37-39
12	**प्रेमचंद के उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार का चित्र** अरुण कुमार साह, खान्द्रा	40-41
13	**अस्मिता तलाशती नारी** सन्दीपना शर्मा, जालन्धर	42-44
14	**राधेमोहन राय के कहानी–साहित्य में प्रकृति चित्रण** नरेश कुमार सिहाग, चेन्नई	45-47
15	**दलित विमर्श** सुशीला, भिवानी, हरियाणा	48-50
16	**डॉ० श्याम सिंह शशि और यायावर साहित्य** शक्ति शर्मा, उतराखण्ड	51-59
17	**जनमानस की कवयित्री – मीरां** सोहनराम, अजमेर	60-62
18	**मध्यकालीन सन्त :– एक सामाजिक परिचय** अरविन्द सिंह चौहान, अजमेर	63-65
19	**हिन्दी साहित्य में स्त्री–विमर्श की भूमिका** वीरेन्द्र भारद्वाज एवं अशोक कुमार मीणा, दिल्ली	66-68
20	**संस्कृत वाङ्.मय में नाट्यशास्त्र की उपयोगिता** माधवी शर्मा एवं संजय मेहरा, खेरली, अलवर	69-70
21	**कल्हण की ऐतिहासिक दृष्टि–कश्मीर के आलोक में** अनिता सेनगुप्ता, इलाहाबाद	71-73

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगाँव

आबेदा बेगम
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.कमला देवी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
राजनांदगाँव

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियों पर आधारित है। ई गवर्नेन्स का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शिता पूर्ण ढंग से शीघ्र कार्य का निर्माण करना है। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं और योजनाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे ही ई गवर्नेस, ई सरकार या डिजिटल सरकार के नाम से जानते हैं। ई गवर्नेस के द्वारा नागरिकों और व्यापारियों को सरल सुगम और महत्वपूर्ण योजनाये प्राप्त होती हैं। ई गवर्नेस के द्वारा अनेक योजनायें बनाई गई है जैसे–ई सेवा, ई नागरिक सेवा, ई चौपाल, ई बुक, ई पोस्ट पेमेंट बैंक इत्यादि।

मुख्य शब्द : ई गवर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

प्रस्तावना

ई गवर्नेस को इलेक्ट्रानिक गवर्नेस, डिजिटल सरकार या ऑनलाइन सरकार के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के जरिए सरकारी सूचनाओं एवं सुविधाओ को आम जनता तक पहुँचाना ही ई गवर्नेस है। आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने यह तर्क संगत कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर. एण्ड पी.जी.) द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) का प्रारंभ किया गया। केन्द्र सरकार ने 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ एन.ईजी.पी. का अनुमोदन किया।

भारत में 1987 से निकनेट (उपग्रह आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क) ई–प्रशासन पर मुख्य बल दिया गया, बाद में सभी जिलो कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण करने राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र की सूचना प्रणाली की शुरूआत की गई। 1990 में राज्य की राजधानियों से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक इंटरनेट से जोड़ा गया। स्त्रोत India.govt.in

ई गवर्नेस को सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए बनाया गया है। जिसका मूल मंत्र है – "एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिये।"

अध्ययन का उद्देश्य

आम आदमी को ई गवर्नेस का अधिक से अधिक उपयोग करने व काम को शीघ्र करने, भ्रष्टाचार से मुक्त रहने की जानकारी तथा आम जनता को डिजिटल सेवा से परिचित करना।

ई गवर्नेस के लाभ या उपयोगिता

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिको, व्यापारियों और समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रहे है। अब लोगो को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हैं। वो घर बैठे सारा काम आसानी से कर सकते है। उदा. बैंक में खाता खुलवाना, पैसा जमा करना, सभी तरह के बिल भुगतान (बिजली बिल, पानी का बिल, टैक्स इत्यादि) इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से कर सकते हैं।

सभी तरह की टिकट बुकिंग, एयर, रेल्वे, बस, टैक्सी, होटल, इत्यादि। सभी तरह की खरीदी ऑन लाइन शॉपिंग के द्वारा की जा रही है। पेमेंट–क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटियम से कर सकते है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य लेन देन सभी ऑन लाइन हो गया है। नौकरी के लिए आवेदन, विद्यार्थी ऑन लाइन प्रवेश हेतु फार्म, रिजल्ट सब घर बैठे कर सकते है।

ई गवर्नेन्स का उद्येश्य

1. भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना।
2. भ्रष्टाचार कम करना।
3. सरकारी कार्यो में गति लाना।
4. आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना, शीघ्र सरल सुविधा देना।

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

5. जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता लाना।
6. आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना।
7. पर्यावरण के लिए लाभदायक।
8. जवाबदेही निश्चित करना।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गांवो और पंचायतो तक ई क्रांति का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेस योजना के तहत इन्दिरा आवास, मनरेगा, समेत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धित योजनाओं का लाभ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। शहरों से गांवो की दूरी कम करने, सभी तरह के केन्द्र राज्य सरकार की सूचना देने सभी गांवो की पंचायतों का ब्राडबैंड से जोड़ने कहा गया है। सरकार ने जनता से संपर्क करने एवं कार्यो को सरल बनाने के लिये ई गवर्नेन्स की कुछ श्रेणियाँ बनायी है, जिससे आम नागरिको को लाभ हो रहा है। इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सीधा संपर्क कर रही है और राज्यों के कार्यो व गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रही है।

ई गवर्नेन्स की श्रेणियाँ

- जी 2 जी सरकार से सरकार
- जी2सी सरकार से नागरिक
- जी2बी सरकार से व्यवसाय
- जी 2ई सरकार से कर्मचारी

जी.टू.जी.(सरकार से सरकार तक)

इसके माध्यम से ई गवर्नेस में एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उदाहरण–किसी अपराधी के बारे में राज्य पुलिस विभाग को जानकारी मिली है तो वह संपूर्ण जानकारी सिस्टम में डाल देता है। उस अपराधी के बारे में देश के हर पुलिस स्टेशन में यह रिकार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता हैं, जिससे अपराधी को कहीं भी पकड़े में आसानी होती है।

इसी प्रकार भारत सरकार राज्य सरकारो को कोई जानकारी देना चाहे तो वेबसाइट पर जानकारी डाल देती है। सभी राज्य सरकार सूचना प्राप्त कर लाभ उठती है।

जी.टू.सी.(सरकार से नागरिक तक)

एक आम नागरिक इसकी सहायता से अपने सरकारी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। उदाहरण– बीमा पालिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकता है। जी.पी.एफ., ई.पी.एफ. सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

जी.टू.बी.(सरकार से व्यवसाय तक)

व्यापारी वर्ग को ई गवर्नेन्स की सुविधा प्राप्त है। वह घर बैठे कई सरकारी कार्यों को आसानी से कर सकता है जैसे– ट्रेडिंग, लाइसेंस के लिये आवेदन वैट के लिए पंजीकरण इत्यादि।

जी.टू.ई.(सरकार से कर्मचारी तक)

इसमें सरकार सरकारी कर्मचारी से आसानी से संपर्क कर सकती है। सरकार को किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी की जानकारी उस विभाग के वेबसाइट के जरिये आसानी से प्राप्त हो सकती है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क करती है।

सी.टू.सी.(नागरिक से नागरिक तक)

इस प्रकार की ई सेवा में नागरिको का पारस्परिक संपर्क होता है। इन श्रेणियों का विकास कर सरकार, ई सेवा के माध्यम से एक ओर–प्रशासन को सशक्त, प्रभावशाली, पारदर्शी बना कर देश के आर्थिक सामाजिक विकास को द्रुत गति से आगे ले जाना चाहती है, वही दूसरी ओर आम जनता के जीवन को ई सेवा से सरल व सुगम बनाना चाहती है। यह देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ई गवर्नेन्स की चुनौतियाँ

ई गवर्नेन्स सरकारी काम काज को गति प्रदान करने का बहुत सरल सुगम तरीका है किन्तु इसे चलाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं :–

1. वेबसाइट की हैकिंग।
2. इंटरनेट की सुविधा सही न होना।
3. फर्जीकाल द्वारा खाते से पैसा निकालना।
4. आधारकार्ड का बचत खाते से जोड़ेने से जानकारी लिक होने का डर।
5. गाँवो में अशिक्षा, इलेक्ट्रानिक उपकरण का ज्ञान न होना।
6. गरीबी के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न होना (उदाहरण– मोबाईल, कम्प्यूटर नेट इत्यादि)।
7. सूचना क्रांति का ग्रामीण निर्धनों पर अल्प प्रभाव।

निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाने, योजनाओं को शीघ्र लागू करने, दस्तावेजों को सुव्यवस्थित साफ्टवेयर में रखने, गांवो से शहरो की दूरी मिटाने में ई गवर्नेस एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सेवा हैं। इसमें सरकार व जनता दोनो सक्रिय रूप से भागीदारी होना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में जहां ई–गवर्नेस से बहुत लाभ हो रहा हैं वहीं कुछ समस्यायें चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होते दिख रहा है परन्तु अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत हैं। जनता कों सचेत हो कर सभी कार्य करने की जरूरत हैं। सरकार की सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *योजना नवम्बर 2013 – पृ. 31–34*
2. *डॉ. फडिया बी.एल. , लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा 2009 पृ. 950*
3. *योजना नवम्बर 2014 डिजिटल डेमोक्रेसी*
4. *मिश्र उमाशंकर – डिजिटल डेमोक्रेसी और पत्राचार योजना नवम्बर 2014*
5. *राष्ट्रीय पोर्टल–20, इंटरनेट से प्राप्त आंकडे*

Reviewed
(P) : 2321-290X * (E) 2349-980X
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Peer Reviewed / Refereed Journal
VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.689
GIF = 0.543
IIJIF = 6.038

UGC S.NO. 40880 Shrinkhla UGC approved/listed

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala

श्रृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

20	**'Women Short –Story Writers of Assam': A Golden Bond of Friendship with the Neighbouring Literature** Agnimitra Panda, Bolpur, West Bengal	92-93
21	**कानपुर नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में महिला शिक्षिकाओं का योगदान** ममता शुक्ला, दिबियापुर, औरैया	94-96
22	**प्राचीन एवम् आधुनिक राम काव्य में 'स्त्री विमर्श'** सन्दीपना शर्मा, जालन्धर	97-100
23	**हिंदी नाटकों में स्त्री अस्मिता का प्रश्न** राज भारद्वाज एवं अशोक कुमार मीणा, दिल्ली	101-104
24	**विकास का दंश झेलती कोयलांचल की महिलाएं** मीना कुमारी, रानीगंज, पश्चिम बर्दवान, पश्चिम बंगाल	105-110
25	**"रिसते रिश्ते" उपन्यास : एक अध्ययन** रूबी जुत्शी, श्रीनगर	111-115
26	**शिक्षा – आज के सन्दर्भ में** नीतू गुप्ता, कानपुर	116-118
27	**सामन्तवादी मानसिकता के खिलाफ मीरा का विद्रोह : एक जन चेतना** सोहनराम, राजस्थान	119-121
28	**मध्यकालीन संतों के काव्यों में सामाजिक चेतना का अध्ययन (राजस्थान के सन्तों के सन्दर्भ में)** अरविन्द सिंह चौहान, राजस्थान	122-127
29	**भूमण्डलीकरण और सांस्कृतिक अस्मिता** हबीब खान, डीडवाना	128-133
30	**आधुनिकता की दौड़ में संस्कृत की उपेक्षा किन्तु समृद्ध भविष्य** मधुबाला मीना, अलवर	134-138
31	**भक्ति का दार्शनिक चिन्तन–पाञ्चरात्रागम के आलोक में** अनिता सेनगुप्ता, इलाहाबाद	139-141
32	**शब्द भावों से परे शख्सियत – डॉ. मधु भट्ट तैलंग** मैनेजर लाल बैरवा, जयपुर	142-149
33	**राव कलाकारों का संगीत शिक्षण में योगदान** संजय कुमार बारेठ, जयपुर	150-153
34	**मेवाड़ लघुचित्र शैली एवं उसमें अश्वों का कलात्मक अंकन** मनीषा खींची एवं इशरत उल्लाह खान, जयपुर, राजस्थान	154-157
35	**राजस्थान में पर्यावरण पर्यटन–समीक्षात्मक अध्ययन (मरू जिला–बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में)** श्रवण कुमार प्रजापत, बीकानेर, राजस्थान एवं संजीव बंसल, नेहर, राजस्थान	158-160
36	**उत्तराखण्ड में औद्योगिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन–सूक्ष्म व लघु उद्योग के संदर्भ में** मंजु जोशी, अरुणाचल प्रदेश	161-163
37	**प्लास्टिक प्रदूषण समस्या एवं समाधान** नागरत्ना गनवीर एवं आबेदा बेगम, राजनांदगांव	164-166
38	**नागरिक अधिकार एवं भारतीय परिदृश्य** कविता देवी, मोर माजरा, करनाल	167-171
39	**सशक्त भारतीय विदेश नीति के लिए मालदीव में शांति जरूरी** प्रभप्रीत सिंह, चण्डीगढ़ एवं स्वाती सोम, हरियाणा	172-175
40	**पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका** मुकेश कुमार बगड़िया, जयपुर	176-180

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* (Part-1) September- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

प्लास्टिक प्रदूषण समस्या एवं समाधान

सारांश

धरती का अस्तित्व खतरे में डालने वाला यह सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यूज एण्ड थ्रो के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग आसानी से करता है किन्तु प्लास्टिक पुरी दुनिया के लिए "परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक है।" प्लास्टिक 100 साल तक नष्ट नहीं होता है। यह नालियों में गिरता है तो नालियाँ चोक (जाम/बंद) कर देता है और जमीन में गिरने से जमीन को बंजर बना देता है। यह मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षियो, समुद्री जीवों, पेड़ पौधो एवं संपूर्ण पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक है। सरकार प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने अनेक कानून बना रही है किन्तु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना बंद नहीं कर पा रहा है। प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक संभव नहीं है लेकिन नागरिको की भी पर्यावरण के प्रति कुछ खास जिम्मेदारी है जिन्हें वे समझदारी से उपयोग करे तो इसके खतरो से काफी हद तक बच सकते है।

मुख्य शब्द : प्लास्टिक प्रदुषण समस्या एवं समाधान।

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव

आबेदा बेगम
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.कमला देवी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
राजनांदगांव

प्रस्तावना

तकरीबन नब्बे साल पहले हमारे जीवन में प्लास्टिक का नामोनिशान नहीं था, पर अब पूरी दुनिया में इसने अपने पाँव पसार लिये है। आज जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो प्लास्टिक से अछूता है। घर के सभी सामान जैसे – बच्चो के खिलौने से लेकर हवाई जहाज तक अर्थात् खाने पीने के लंच बाक्स, दूध, पानी की बोतले, पेन, पेंसिल, बैग, कपड़े, जूते, चप्पल, अलमारी, टेबल, चेयर, पलंग इत्यादि एवं इलेक्ट्रानिक चीजो में मोबाइल, टी.वी., लैपटाप, फ्रीज, वाशिंग मशीन, मोटर कार, हवाई जहाज इत्यादि सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। वास्तव में यह हमारे जीवन के लिए एक ओर सुविधा जनक है तो दूसरी ओर प्रदूषण फैला रहा है। संपूर्ण प्राणी जगत एवं प्रकृति के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अतः इसका इस्तेमाल कम से कम करने का हमे संकल्प लेना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्लास्टिक से होने वाले खतरे से आगाह करना।
2. प्लास्टिक का उपयोग जहाँ अत्यधिक जरूरी है वहीं करना (जैसे–इलेक्ट्रानिक्स चीजो में), सामान लाने ले जाने में न करना एवं प्लास्टिक में गरम खाने की चीजे न रखने के लिए जागरूकता बढ़ाना।
3. प्लास्टिक को कही भी फेकने से रोकने के लिए जागरूकता लाना।
4. प्लास्टिक कचरे का उचित निस्तारण (उपयोग)

प्लास्टिक की शुरूआत ईसा पूर्व 1600 में प्राकृतिक रूप से रबर के पेड़ो से मिलने वाले रबर माइक्रोसेल्यूलोज, कोलेजन और गैलाइट के मिश्रण से गेंद (बाल), बैंड और मूर्तियां बनाने में किया गया किन्तु आधुनिक प्लास्टिक का श्रेय ब्रिटेन के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स को जाता है जिन्होंने प्लास्टिक का उपयोग सजावटी समान बनाने में हाथी दांत जैसा दांत बनाने के लिए किया। इनका उद्देश्य हाथियों की हत्या को रोकना था। उन्होंने 1856 बर्मिंघम में इसका पेंटेट भी करवाया। लेकिन यह किस्म अत्यधिक लचीली नहीं थी। सन् 1900 में प्लास्टिक क्रांति आई जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह सिंथेटिक रूप में सामने आया।[1]

सच्चे प्लास्टिक बनाने का श्रेय 1907 में बेल्जियम मूल के अमरीकी वैज्ञानिक लियो एस.बैकलैंड को जाता है। उन्होंने कहा था "अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा यह अविष्कार (बैकेलाइट) एक नये भविष्य की रचना करेगा।" ऐसा हुआ भी इसीलिए टाइम्स मैग्जीन ने अपने कवर पेज में बैकलैंड की तस्वीर छापी और लिखा–"ये न जलेगा ना पिघलेगा"। 2 वास्तव में बैकलैंड इलेक्ट्रिक मोटरो और जेनरेटरों में तारों की कोटिंग के लिए एक पदार्थ की खोज कर रहे थे जो गोंद जैसा चिपचिपा हो और सूखने पर पपड़ी या सख्त हो जाता हो।

इनका प्रयोग सफल रहा और उन्होंने प्लास्टिक बनाने वाली कम्पनी का पेटेंट हासिल कर लिया। प्लास्टिक का आणविक भार अत्यधिक होता है। इसी कारण यह किसी भी वातावरण में खराब नहीं होता हैं। अत्यधिक सुविधाजनक यह प्लास्टिक दूध, दवा, पानी, तेल से लेकर सब चीजो के लाने लेजाने (सुरक्षित) रखने में हमारे घर, दुकान, ऑफीस सर्वत्र घूसपैठ कर चुका है। आज हमारी दिनचर्या में इतनी अधिक प्लास्टिक की चीजें उपयोग मे लायी जाती हैं कि अगर किसी दिन इनका उपयोग न किया जाए तो शायद दुनिया अधूरी लगेगी। हम अंधाधुंध प्लास्टिक का इस्तेमाल कर पर्यावरण को इतने गंभीर खतरे में डालते जा रहे हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। हर साल दुनिया में पाँच सौ अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। हर मिनट में दस लाख से ज्यादा बैग इस्तेमाल कर फेंक दिए जाते हैं।[3] पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 88 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है। इसी कारण समुद्री जीव हर साल अत्यधिक संख्या में दम तोड़ रहे है।[4]

1960 के दशक की तुलना में आज 20 गुना अधिक प्लास्टिक बन रहा है। जिस तेजी से प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 2050 तक 33 अरब टन प्लास्टिक और बना चुके होंगे जिसका बड़ा हिस्सा महासागरो में पहुंच जायेगा और सदियों तक वहीं बना रहेगा। अगर वर्तमान में समुद्रों में पड़े प्लास्टिक कचरे को साफ करने की बात करे तो जिस रफ्तार से काम चल रहा है करीब 800 साल लग जायेंगे।[5] प्लास्टिक के कारण 1200 से ज्यादा समुद्री जीवो की प्रजातियाँ खतरे में है।

हम जिस प्लास्टिक का उपयोग करते है उसमें 50 फीसदी सिंगल यूज या डिस्पोजेबल प्लास्टिक है। इसमें पानी की बॉटल, चम्मच, कटोरी, प्लेट ग्लास जैसी चीजे हैं। हर मिनट में 10 लाख पानी की प्लास्टिक बोतले खरीदी और पीकर फेकी जा रही हैं। 2017 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक अनुमान में बताया कि भारत में प्रतिवर्ष करीब 25,940 टन प्लास्टिक बनाया जा रहा है।[6]

भारत में पहले थैले या बैग लेकर लोग मार्केट जाते थे किन्तु अब थैला या बैग ले जाना प्रेस्टीज ईसू बनते जा रहा है। आज कोई भी शहरी व्यक्ति सामान लेने जाता है तो सामान लाने के लिए कोई तैयारी कर के नहीं जाता। चाहे जितना सामान लाना है सब्जी, फल, कपड़ा, बर्तन, सब पॉलिथीन में भर कर लाते है और फिर उसे खाली कर फेंक देते हैं। प्लास्टिक का उपयोग आसान और सस्ता होने के कारण इसका इस्तेमाल क्रेता और विक्रेता दोनो कर रहे हैं।

करीब सौ सवा सौ साल की प्लास्टिक की यात्रा ने पिछले 40–50 वर्षो में सबसे ज्यादा तरक्की की है। 1950 से प्लास्टिक का चलन तेजी से बढ़ा है। करीब 20 लाख टन से 40 टन करोड़ प्रोडक्ट हमारे जीवन मे घुसपैठ कर चुके है।

प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। प्लास्टिक चूँकि सालो खराब नहीं होता है साथ ही विद्युत का कुचालक है, पिघलने पर मन चाही आकृति में ढाल कर सामान बनाये जाते है, अतः इसका उपयोग बहुतायत से होता है। टूटने फूटने का भी डर नहीं है, हर चीज सुरक्षित हो जाती है आज के युग को प्लास्टिक संस्कृति का युग कहे तो भी कोई अतिसंयोक्ति नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ 85 प्रतिशत पैकिंग प्लास्टिक में कर रहीं है जिसमें कवर से लेकर रस्सी तक उसी की होती है।

प्लास्टिक पुस्तक की लेखिका सुजैन फ्रीनकेल लिखती है कि हम एक दिन की दिनचर्या में 24 घण्टे में 196 प्लास्टीक की चीजो का इस्तेमाल करते हैं जबकि गैर प्लास्टिक चीजो की संख्या 102 रहती है।[7] प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। यह सुविधा जनक है किन्तु उपयोग के बाद जब फेंका जाता है तो सब जगह विषैला हो जाता है। धरती पर पड़ने से धरती बंजर हो जाती है और नालियों में पड़ने से नालियाँ जाम। जानवरों के खाने से जानवर तड़प कर मर रहे हैं, समुद्री जीव खतरे में है। भारत में प्रतिदिन 20 गायें पॉलिथीन खाने से मर रही है। प्रतिवर्ष मुंबई शहर में पानी ही पानी भरने का एक मात्र कारण नालियों का प्लास्टिक से जाम होना है। विशेषकर मुंबई में 1998 में भयंकर बाढ़ का एक मात्र कारण नालियों में पालिथीन का जाम होना था। इस प्रकार भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्लास्टिक एक गंभीर समस्या बनते जा रहा है। भारत में प्लास्टिक बनाने में 30 हजार से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई है।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत में 60 शहर रोजाना 3500 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई कलकत्ता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकाला जा रहा है।[8] भारत में 80 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है।

प्लास्टिक से खतरा क्या है? –

1. प्लास्टिक व पालिथीन दोनो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
2. प्लास्टिक के डिब्बों में गरम खाना रखने से यकृत कैंसर और भ्रूण संबंधी गंभीर बीमारियाँ हो रही है साथ ही दमा/अज्लाइमर का खतरा बढ़ रहा है।
3. प्लास्टिक की बोतलो में पाया जाने वाला खास तत्व थैलेटस की वजह से हॉर्मोनो का रिसाव करने वाली ग्रंथियों का क्रियाकलाप बिगड़ जाता है।(9)
4. जानवरो के पेट फूलने व मरने का एक बड़ा कारण उनका प्लास्टिक की थैलियों में रखा खाद्य पदार्थ खाना है, वे थैलियों सहित खा लेते हैं। अहमदाबाद में 100 किलोग्राम कचरा एक गाय के पेट से निकाला गया जिसमें ज्यादा पॉलिथीन की थैलियाँ थी।(10)
5. गिर के जंगल में शेर के पेट से भी पॉलिथीन की थैलियाँ निकाली गई जो बहुत खतरनाक है।
6. अकेला अमेरिका प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों में हर साल 340 अरब डालर खर्च कर रहा है।
7. प्लास्टिक सौ वर्ष तक नष्ट नहीं होता और इसे जलाने से विषैली गैंसो से ओजोन परत को नुकसान होता है।

8. उत्पादन से इस्तेमाल तक तथा बाद में (कचरा) सभी अवस्था में समुचे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक है।
9. प्लास्टिक की वजह से हर साल एक लाख समुद्री जीव मर रहे है।
10. वाटर रीचार्जिंग में बाधक।
11. 40% नाले, नालियाँ, नल, पॉलिथीन के कारण जाम हो रहे हैं।
12. नालियों के जाम होने से मच्छर, वायरस, डेंगू, मलेरिया और पीलियाँ जैसी संक्रमक बीमारियाँ हो रही हैं। छ.ग. के भिलाई शहर में (दो माह में) 43 मौते डेंगू से हुई है।
13. हर साल देश में 56 लाख टन प्लास्टिक के कचरे का नया पहाड़ खड़ा हो रहा है। (11)

सरकारी प्रयास

खतरनाक प्लास्टिक पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए अनेक कानून बनाये है किन्तु प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में सिंगल यूज वाला प्लास्टिक का हर सामान बैन किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने अनेक कानून बनाये हैं–

1. इस्तेमाल किए जाने वाली प्लास्टिक के उत्पादन और प्लास्टिक की मोटाई की जानकारी थैली पर छापना होगा।
2. दुकानदारों को खुली थैलियों में सामान बेचने पर पाबंदी है।
3. दुकानदारों को "वापस खरीदो" योजना के तहत ग्राहको से पैकेजिंग में बेचे गये सामान की थैली वापस खरीदनी होगी।

प्लास्टिक बैग, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कटलरी और थर्मोकोल के समान पर प्रतिबंध होगा।

सुझाव

1. प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल से बचना चाहिए।
2. गरम चीजें जैसे खाना, दूध, पानी, चाय, प्लास्टिक में न रखें।
3. प्लास्टिक की रिसाइकलिंगि को बढ़ावा देना चाहिए।
4. जवाबदेही तय होना चाहिए।
5. पालिथीन का उपयोग बंद करने में महिलाओं का सहारा लिया जा सकता है। वे संकल्प ले तो काफी हद तक पालिथीन प्रतिबंधित करने में कामयाब हो सकते है।
6. सभी जगह पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। लोगो को कपड़े या पेपर के बैग का उपयोग करे।
7. पालिथीन के कचरे से सड़क बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। सड़के मजबूत होगी।
8. मकानो केनिर्माण कार्य में रेत (बालू) की जगह प्लास्टिक का आंशिक रुप से उपयोग किया जाये।
9. मनुष्य को स्वयं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर्यावरण हमारी आवश्यकता है, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी मनुष्य स्वस्थ रहेगा इसे समझने की जरुरत है।
10. प्रतिबंधित पालिथीन का उपयोग करने वालो के लिए दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। पालिथीन कहीं भी फेका न जाये इस पर भी कानून बनना चाहिए।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, व्यापारिक संगठनो एवं आम नागरिक को संकल्पबद्ध होकर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। धरती का श्रृंगार हमारे पेड़ पौधे, जीव जन्तु, समुद्र, नदी, नाले सभी स्वच्छ रखने होंगे। जिस तरह पालिथीन का उपयोग हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाको में बैन है वैसे ही भारत में सभी जगह होना चाहिए। हिमाचल में पालिथीन में कोई सामान नहीं मिलता है। सरकार द्वारा बोर्ड लगाये गये है जो भी पॉलिथीन फेकते पाया गया उसे 5000 रूपये जुर्माना है। प्रत्येक टैक्सी या कार में डस्टबीन रखना आवश्यक है वरना तुरन्त फाईन देना पड़ता है। अतः पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनो को स्वस्थ रखना है तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। स्वयं में सुधार लाने की जरूरत है तभी हम शुद्ध सांस ले पायेगें वरना वो दिन दूर नहीं जब मुंह पर मास्क और पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेण्डर ले कर चलना होगा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2018 मनाया गया इसका विषय था "प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएँ" इसमें सरकारों, उद्योगो और जनसमुदाय से आग्रह किया गया था कि वे प्लास्टिक से नाता तोड़े क्योंकि प्लास्टिक परमाणु बम है जिससे पृथ्वी को बचाना है मानव जगत को बचाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *विज्ञान प्रगति/पर्यावरण विशेषांक/जून 2018/पृ.10*
2. *वही पृ.11*
3. *दैनिक भास्कर/पर्यावरण दिवस विशेष/5 जून 2017*
4. *विज्ञान प्रगति/प्लास्टिक से कराहते महासागर/जून 2018/पृ.97*
5. *दैनिक भास्कर/5 जून 2017*
6. *दैनिक भास्कर/एम.वैकया नायडू उपराष्ट्रपति/24 अप्रैल 2018*
7. *विज्ञान प्रगति/जून 2018/पृष्ट 12*
8. *वही/पृष्ट–14*
9. *विज्ञान–प्रगति/जून 2018/पृ.15*
10. *वही पृ.13*
11. *दैनिक भास्कर/5 जून 2017*

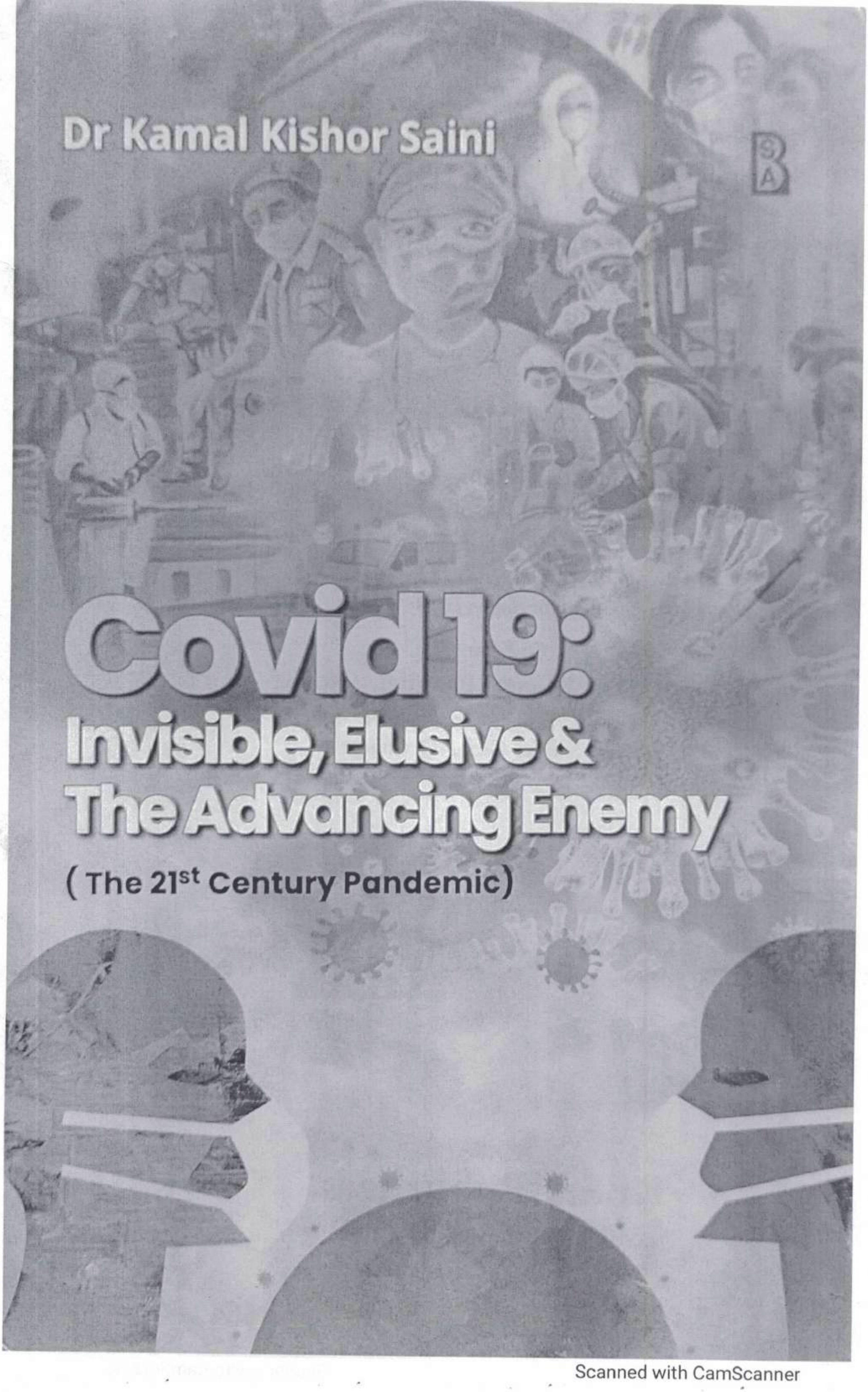

Scanned with CamScanner

Contents

1. COVID-19: History and Vaccination 1
Radheshyam Thakur, Lalitpur, Kathmandu (Nepal)

2. Hospital Preparedness for Managing COVID-19 6
Dr. Sushila Saini, Jaipur, Rajasthan
Dr. Seema Gupta, Jaipur, Rajasthan

3. Prevention and Disinfection: COVID-19 14
Dr. Chetan Saini, Memphis, TN (USA)
Dr. Mahaeswaran Dhanasekaran, Rochester (USA)

4. Corona Virus Disease 2019: Prevention and Disinfection 19
Iti Sharma, Pilani, Rajasthan

5. Preventive Measures and Disinfection Strategies against Corona Virus Disease: An Overview 27
Mrs Ritu Devi, Dibrugarh, Assam

6. COVID and Cancer: A Double edged Sword 37
Dr. Annu Rajpurohit, Mumbai, Maharashtra

7. Fight against Corona: A Humble Request on how to Eradicate Covid-19 40
Dr. Anil Patria, Jaipur, Rajasthan

8. Hospital Preparedness for COVID19: An Overview 44
Mrs Manisha Devi, Agartala, Tripura

9. Impact of COVID-19 on our Life Style 53
Kamlesh Kumar, Plano, Texas (USA)
Medha Singh, Plano, Texas (USA)

10. Implications of Covid-19 on Global and India Economy: Overview 58
Sukhbinder Singh, Bangkok (Thailand)

11. Economic and Social Impacts of COVID-19 62
Dr. Vikram Lamba, Haryana

12. Impact of COVID-19 on the Global Economy 72
Vivek Kumar Tiwari, Lucknow, Uttar Pradesh

Scanned with CamScanner

कोविड-19 का स्कूल शिक्षा अध्यापन एवं छात्रों पर प्रभाव

■ *डॉ. नागरत्ना गनवीर**

"शिक्षा एक ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने में कर सकते हैं।"

—**नेल्सन मंडेला**

कोरोना वायरस, (कोविड-19) एक संक्रमण बीमारी है जिससे दुनिया के 197 देश संक्रमित हो चुके हैं और लाखों की संख्या में मौते हुई हैं। यह बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खाँसने या सांस लेने से, आँख, नाक और मुँह द्वारा फैलती है। विश्व के कई देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या 1.50 लाख से 20 लाख तक हो गई है भारत में 2.5 लाख से अधिक संक्रमित हो गये है। अमरीका जैसे विकसित देश में कोरोना संक्रमण से एक लाख से अधिक मौते हुई है तथा भारत में संक्रमण से मौतो का आंकडा 5,739 (5 जून, 2020 तक) है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा चार चरणों में लॉकडाउन किया गया—

1. पहला चरण — 25 मार्च से 14 अप्रैल (21 दिन)
2. दूसरा चरण — 15 अप्रैल से 3 मई (19 दिन)
3. तीसरा चरण — 4 मई से 17 मई (14 दिन)
4. चौथा चरण — 18 मई से 31 मई (14 दिन)

भारत में कुछ 68 दिन का लॉकडाउन रखा गया। इस लॉकडाउन का प्रमुख कारण कोरोना वायरस के चैन को तोड़ना (21 दिन का पहला लॉकडाउन) था। किन्तु संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई और सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। इसका उद्देश्य लोगों को बचाना और संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उनका इलाज कराना ताकि यह संक्रमित बीमारी का कोई दूसरे शिकार न हो। पूरी दुनिया पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव पड़ा। दुनिया के मार्केट, शॉपिंग माल, फैक्ट्रियाँ, मंडिया, थिएटर, खेल मैदान,

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner

सरकार ने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए फरवरी 2017 में शिक्षा के अधिकार में संशोधन किया। सरकार ने बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव किया। NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, यह एक योग्यता पर आधारित मूल्यांकन चालू किया गया।

शिक्षा में इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग

भारत में समय के साथ-साथ शिक्षा को विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य लोगों के जीवन को पारदर्शी, आरामदायक और खुशहाल बनाना है। शिक्षा जगत में सरकार द्वारा यह सुधार हुआ कि यदि युवाओं में जब वैज्ञानिक सोच विकसित होगी तो वे वास्तविक जीवन में आम लोगों के सामने आने वाली हर समस्याओं का समाधान सरलता से करने में सहयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा—"नये भारत को तकनीक और वैज्ञानिक सोच की जरूरत है ताकि हम अपने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को नई दिशा दे सकें।" उन्होंने कहा मुझे जानकर खुशी हो रही हैं कि नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग बेहतर होकर 52वें पायदान पर पहुँच गई है। इन उपलब्धियों के लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ।[2]

स्कूल शिक्षा में कुछ मुख्य सुधार एवं नवाचार

1. **एनडीएल**—राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इसकी शुरुआत 19 जून 2018 में की गई, इसमें शिक्षण सामग्री वीडियो, आडियो, पुस्तकें व्याख्यान सब ऑनलाइन है।
2. **निष्ठा**—एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (एनआईएसटीएएच) निष्ठा नाम दिया गया अर्थात् राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नत पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 42 लाख शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईइटी) के सदस्यों, ब्लाक संसाधन समन्वयकों और कलस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमता का निर्माण करता है। इसमें सभी राज्यों केन्द्रशासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गये।[3]
3. **ध्रुव**—यह नवाचार शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच है। विज्ञान, कला, रचनात्मक लेखन में विशिष्टता प्राप्त विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं।
4. **शगुन**—स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने और सर्वसमावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार के सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों और वेबसाइटों का एक जंक्शन बनाया है। इसमें पूरे देश के 15 लाख स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है। पोर्टल

Scanned with CamScanner

एक्टिविटी 35 से बढ़ कर 65 प्रतिशत हो गई। ऑनलाइन कोर्सेस में तीन गुना इजाफा हुआ है। **भारत सरकार Online Education के लिए ई लर्निंग के लिए** चार पोर्टल बनाये गये थे जिसमें **ईएलआईएस, स्वयं, दीक्षा, नेरोएर** इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेस व क्लासेस के लिए **6 प्लेटफार्म—बायजूस, कोर्सेरा, यूडिमी, अनएकेडमी, टॉपर, वैदांतु** जैसे प्लेटफार्म टीचर्स और स्टूडेंटस को जोड़ने का काम करता है। इन पोर्टल पर ई बुक्स, पाठ्यसामग्री, आडियो, वीडियों, लेक्चर, प्रतियोगी परीक्षओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन लेक्चर, व पाठ्यसामग्री से भरे हुए है। कॉलेजो में आनलाइन नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार क्वीज, जूम एप एवं वाट्सएप और गूगल एप के माध्यम से हो रहे है। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन डांस, पेंटिग, ड्रेस, सिंगिंग ऐशे काम्पीटिशन करवाया जा रहा है तथा विजेताओं को ई-सर्टिफिकेट दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने **ऑनलाइन पोर्टल—'पढ़ई तुहर दुआर''** लांच किया। छ.ग. के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि—''अब कोई शिक्षक किसी एक स्कूल का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का शिक्षक होगा।'' लॉकडाउन के साथ ही आने वाले समय में बच्चों की निरंतर पढ़ाई में यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित होगा।'' इस ई-लर्निंग प्लेटफार्म में ऑनलाइन इंटरएक्टिव कक्षाओं के जरिए शिक्षक और बच्चें अपने घरो से ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस पोर्टल में होमवर्क देने तथा होमवर्क को ऑनलाइन जांचने की सुविधा भी है। जूम एप के माध्यम से ऑनलाइन इंटरेएक्टिव कक्षाएँ होगी। इन ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक पढ़ाएँगे और बच्चे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का यह अनुभव क्लास की शिक्षा जैसा है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी यह पोर्टल लगातार उपयोग होगा। यह कार्यक्रम वास्तव में छ.ग. के शहरी व दूरस्थ अंचलो के लिए भी बहुत उपयोगी रहा।

छ.ग. में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट cgschool.in में कक्षा एक से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई संसाधन उपलब्ध कराये गये।[6] केन्द्र सरकार के अनेक ऑनलाइन (शिक्षा संबंधी) पोर्टल, प्लेटफार्म का भी विद्यार्थियों ने (लॉकडाउन में) उपयोग कर पढ़ाई जारी रखा। सी.जी. स्कूल पोर्टल में 95 फीसदी स्कूलों के शिक्षक छात्र से जुड़ चुके है। छ.ग. में cgschool.in वेबसाइट पर पंजीकृत स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 20,83,794 तथा कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या 1,66,247 है। पंजीकृत स्कूल शिक्षक-1,97,801, पंजीकृत कॉलेज शिक्षक 6,440।[7]

सभी शिक्षक अपने वीडियों आडियों, पाठ्यसामग्री, cgschool.in वेबसाइट पर अपलोड कर चुके है। उसका फायदा दूर-दूर के गाँवों के बच्चों को भी हो रहा है।

परीक्षा पर प्रभाव

कोरोना वाइरस के कारण 10, 12वीं की कुछ परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई। जो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई में संभावित है। परीक्षाओं की व्यवस्था के लिए कहा गया है कि

Scanned with CamScanner

जो विद्यार्थी जहाँ है उसी परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा दे सकता है। समय पर रिजल्ट नहीं आ पाये, जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ नीट, जेई, पी.ई.टी, कैट की परीक्षा मई में होती थी और जून में नया सत्र प्रारंभ हो जाता था, वह इस महामारी के कारण नहीं हो पाया। ये परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह तक संभव है और नये सत्र सितम्बर तक प्रारंभ होने की संभावना है।

भारत में कोरोना मे निरन्तर बढ़ते हुए केस लगभग 2 लाख 50 हजार तक (4-6-2020) भयावह है। अत: "जान है तो जहान है" यह बात बिल्कुल सच है। कई देशों ने स्कूल खोले लेकिन उन्हे एक दिन में ही बंद करना पड़ा। भारत में, केरल में नये सत्र की शुरूआत । जून से ऑनलाइन कक्षाएँ प्रारंभ हो गई हैं।

निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई

निजी कोचिंग संस्थाओं ने भी कोरोना वायरस के चुनौतिपूर्ण दौर में पीएमटी, जेई, पीपीटी, पीपीएचटी, कैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया। इसका फायदा करीब 80 हजार छात्रों को हुआ। प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं ने ऑनलाइन क्रैश कोर्स से लेकर ऑनलाइन स्कालरशिप की शुरुआत एईएसएल के माध्यम से कर चुके हैं। उसमें टीचर ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करते हैं। वे डिजिटल पेन का भी उपयोग करते है।[8]

पेड वेब पोर्टल पर ऑनलाइन शिक्षा

आर्थिक पिछड़े छात्रों को फ्री कंटेट उपलब्ध है। स्वयं पोर्टल को 50 हजार विद्यार्थियों ने उपयोग किया। इसी प्रकार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (लॉकडाउन के समय) 90 हजार से एक लाख स्ट्राइक रोज हो रही है।[9]

ऑनलाईन एजुकेशन चैनल्स फ्री

कोरोनावायरस काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई निरन्तर जारी रहे इसलिए टाटा स्काय ने अपने चैनल्स नं. 756 पर फ्री एजुकेशन दिखाया जा रहा है। जो विद्यार्थी दूर ग्रामीण अंचलों में पढ़ते हैं, जिनके पास मोबाईल, कम्प्यूटर नहीं है, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एम.एच.आर.टी.) की ओर से चलाए गये फ्री चैनल्स हैं।

कोरोना की इस महामारी में भारत में ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान साबित हुआ है। सभी शिक्षक विद्यार्थी टेक्नोलॉजी से जुड़ गये हैं और यह समय की माँग भी है। डिजिटल तकनीकी के विकास में भारत ने बहुत उन्नति की और पूरी दुनिया इसको लोहा मान रही है। अमरीका के बाद डिजिटल तकनीकी के, शिक्षा में उपयोग के मामले में भारत का दूसरा नंबर है लेकिन कोरोना काल में शिक्षा जगत में कई चुनौतियाँ भी देखने मिली—

1. कई विद्यार्थियों के पास एनराइड फोन नहीं है। नेटवर्क का प्राब्लम गाँव में अधिकतर देखने मिलता है।

Scanned with CamScanner

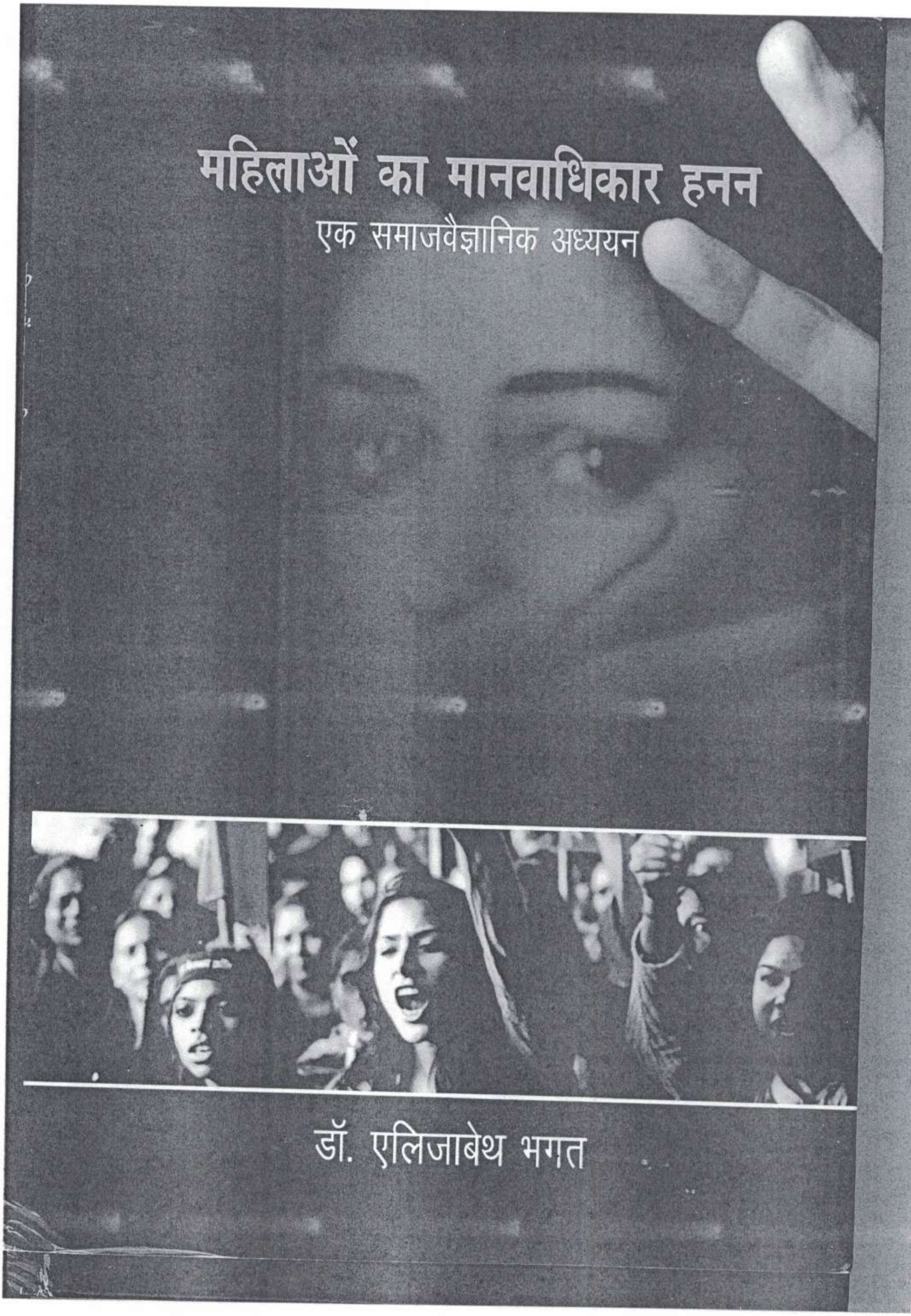
महिलाओं का मानवाधिकार हनन
एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन
डॉ. एलिजाबेथ भगत

महिलाओं का मानवाधिकार हनन
एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ. एलिजाबेथ भगत

AKHAND

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
एल–9ए, प्रथम तल, गली न. 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955 & 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

महिलाओं का मानवाधिकार हनन
एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन

संस्करण : 2019
© लेखक
ISBN: 978-81-939343-1-9

इस सम्पादित पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

प्रस्तुत पुस्तक महिलाओं का मानवाधिकार हनन पर आधारित है। किसी भी देश का विकास एवं प्रगति का निर्धारण उस देश की महिलाओं की स्थिति, उनकी शैक्षणिक दशा, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय, कानून एवं नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका तथा उनके सामाजिक अधिकारों द्वारा ही होता है। यद्यपि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हैं, किन्तु पुरुष प्रधान समाज में महिला केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से आदरणीय व श्रद्धास्पद रहीं है। भारतीय पृष्ठभूमि में वैदिक काल जिसे स्वर्णिम काल कहा जाता है छोड़कर उत्तर वैदिक काल से महिला के सम्माननीय पात्रता में ह्रास के चिन्ह प्राप्त होते हैं और तो और मध्य युग में महिलाओं की दशा निम्नतर होती चली गई ।

डॉ. एलिजाबेथ भगत का जन्म 18 मई 1968 को जशपुर जिले के एक छोटे से ग्राम ऊँचडीह मरियम टोली में हुआ। आपकी शिक्षा एम.ए. (समाजशास्त्र) एवं पी.एच.डी. है। आप शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांदगॉव, जिला : राजनांदगॉव (छ.ग.) में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में 24 वर्षों से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं इस कारण सामाजिक समस्याओं के विभिन्न कारणों पर विचार एवं अध्ययन कर समाधान के तरीके निकालने में गहरी रूची रखती हैं। आप स्वयंसेवी संस्थाओं का भी समय–समय पर आर्थिक मदद करती हैं। वर्तमान में समाज की ज्वलन्त समस्या जैसेः– वृद्धजनों की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों का तथ्य संकलन कर समाधान हेतु परिवार व समाज को जागृत करने में प्रयत्नशील हैं। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव संबंधी इनकी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का शोध पत्र, दो राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र हैं, तथा अब तक 35 शोध संगोष्ठियों में आप भाग ले चुकी हैं, इसके अलावा आप समाजशास्त्र विषय के स्नातकोत्तर प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक के रूप में कार्य करती रहीं हैं।

आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रूचि के कारण इमेट विश्वविद्यालय (अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त) बैंगलोर से डॉक्टर ऑफ टूथ (डी.टी.एच.) की उपाधि प्रदान की गई है ।

AKHAND

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
Distributors, Library Supplier, Online Bookstore & Exporter
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

ISBN 978-81-939343-1-9
9 788193 934319

₹500

ISBN: 978-81-937096-7-2

Environmental Ethics
A Need of Human Concern

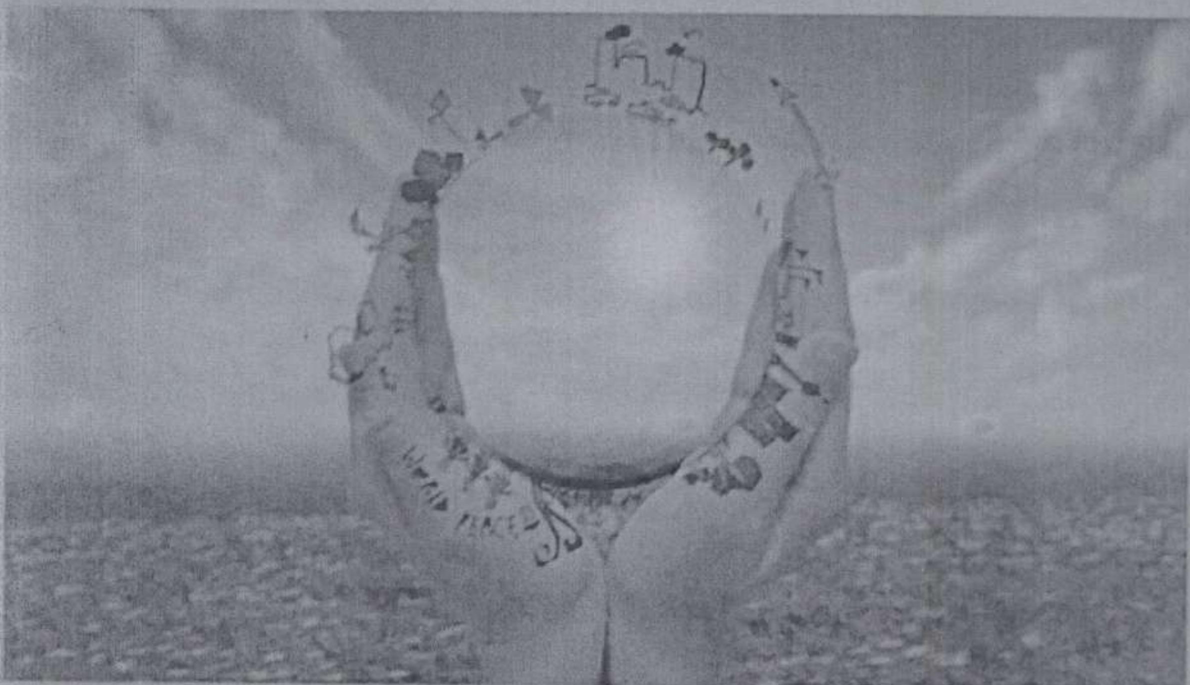

Editor
Dr. Poonam Vij

Scanned with CamScanner

ISBN
978-81-937096-7-2

Scanned with CamScanner

ISBN	:	978-81-937096-7-2
Price	:	270 INR
	:	135 USD
Copy Right	:	Publisher
Editor	:	Dr. Poonam Vij
Edition	:	1st Edition, March, 2019
Publisher	:	Social Research Foundation 128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur (U.P.)
Cover Design	:	Dr. Rajeev Mishra
Laser Type Setting	:	Bhawana Nigam
Cover Clips Source	:	Internet
Printed By	:	Social Research Foundation Kidwai Nagar, Kanpur (U.P.)
Contact	:	9335332333, 9839074762
E-mail	:	socialresearchfoundation@gmail.com
Website	:	www.socialresearchfoundation.com

Scanned with CamScanner

8. पर्यावरण के विभिन्न आयाम तथा जल प्रदूषण के विशेष परिप्रेक्ष्य में 77-88
बृजमोहन मीना, राजगढ़, अलवर

9. पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका 89-101
मुकेश कुमार बगड़िया, जयपुर

10. पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व 102-112
नागरत्ना गनवीर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
शा.शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय
राजनांदगांव, छत्तीसगढ, भारत

सारांश

पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। धरती इतना देती है कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन हर व्यक्ति के लालच को वह पूरा नही कर सकती है। मनुष्य हर साल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहा है। इसी गति से खपत होती रही तो 30 से 40 सालों में धरती पर कोई जगह ही नही बच पायेगी। मनुष्य प्रकृति का दोहन नही, शोषण करते जा रहा है। परिणामतः सर्वत्र पर्यावरण प्रदूषण फैलते जा रहा है। प्रदूषण के कारण मौंतो के आंकड़े निरन्तर बढ़ते जा रहे है। प्रदूषण से सांस की बीमारियाँ ह्रदय व फेफड़े के कैंसर, हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ग्रीन हाऊस गैस का उत्सर्जन, ओजोन परत में छेद जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके भयंकर "खतरनाक" परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्सइड की अधिकता से संपूर्ण प्राणी एवं वनस्पति जगत पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे विकास

Scanned with CamScanner

पर्यावरण प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है बल्कि अनेकों कारण हैं जिस पर अंकुश की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) की एक रिर्पोट के अनुसार दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों मे भारत के 14 शहर कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला, जोधपुर, शामिल है।(1) W.H.O. द्वारा प्रकाशित पत्रिका, जेनेवा में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कानपुर पहले नंबर पर एवं दिल्ली छठे स्थान पर है। इस रिपोर्ट की खास एवं चिन्ताजनक बात यह है कि पर्यावरण प्रदूषण से प्रतिवर्ष दुनिया भर में 70 लाख मौंते होती है, जिसमें से सबसे अधिक मौंते भारत में 24 लाख (34%) होती है। कुछ वर्षो से दिल्ली में ठंड के मौसम में (नवम्बर , दिसम्बर) ऐसा वातावरण बन जाता है कि 25 से 30 दिनों तक सूर्य की रोशनी (धूप) ठीक से पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती। बदली जैसा दिखाई देने वाला स्मॉग (जहरीला धुँआ) के कारण अनेक बीमारियां कैंसर, हार्ट अटैक, खांसी आँखों में जलन इत्यादि होने लगती है।

विगत वर्ष 2017 (नवम्बर, दिसम्बर माह) में कई कारो की एक साथ टक्कर हुई उसमे बहुत जानमाल का नुकसान हुआ। सरकार द्वारा ऐसी विकट स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह के निर्माण कार्य रूकवाये जाते हैं एवं पेड़ों को पानी से धुलवाया जाता है। 2018 में (नवम्बर) भी स्मॉग के कारण सरकार को इन्हीं प्रक्रियाओं से प्रदूषण कंट्रोल करना पड़ा। दिल्ली में विषैले धुंए को कंट्रोल करने और वातावरण को स्वच्छ रखने कारों के लिए "आर्ड इन वन" सिस्टम लागू किया जाता है।

Scanned with CamScanner

विगत वर्षों में केदारनाथ बद्रीनाथ में बाढ़ के कहर से बहुत अधिक जनधन की हानि हुई जिसे भुलाया नही जा सकता। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से ओज़ोन परत में छेद, हो रहा है जो मनुष्य, पशु–पक्षी, पौधे सभी के लिए हानिकारक है। ओज़ोन परत वातावरण के ऊपरी सतह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। बढ़ते तापमान के कारण पानी का जल स्तर घटते जा रहा है। वनों की कटाई से उपजाऊ मिट्टी हवा में उड़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन उपयोग से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। जिससे प्रतिवर्ष 1.9 करोड़ लोग समय से पहले मृत्यु के आगोश में समा जा रहे है।[3] दिल्ली में कैंसर से प्रतिवर्ष 6000 ''छ. हजार'' लोंगों की मौत हो रही है। 2011 की एक रिर्पाट के अनुसार दिल्ली में कैंसर से 9925 मरीजों की मृत्यु हुई ।[4]

भारत में दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी हृदय संबंधी बीमारियों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है। वातावरण में धूल और धुंये के प्रदूषित कण फेफड़े में फिल्टर नहीं हो पाते है। वे खून के साथ धमनियों में चिपक कर रक्त का थक्का बनाने लगतें है। इसके अलावा बढ़ती हुई गर्मी के कारण मलेरिया,डेंगू,खसरा,खूजली,स्वाईन फ्लू जैसी बिमारियाँ कभी भी हो रहीं हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने से जीव जन्तुओं की 47,677 विशेष प्रजातियों में 15,890 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। करीब 1147 प्रकार की मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।[5]

गंगा जैसी पवित्र नदी जिसमें 100 करोड़ लोगो की श्रध्दा है आज भी हम उसे बचाने में असमर्थ है। नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (N.G.T.) ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया है। अभी भी हालात खराब है।[6] एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण

Scanned with CamScanner

खतरा बनते जा रहें। दुनियां को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की सबसे ज्यादा चिंता हैं।

सर्वप्रथम 1970 में न्यूयार्क में अर्थ डे मनाया गया। जून 1992 में प्र्यावरण और विकास पर रियो डिजनेरियो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें उन्होंने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की अनिवार्यता पर ध्यान देने मजबूर किया। भारत सहित दुनिया के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता तथा धरती बचाने का संकल्प लिया।

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.)

भारत में पर्यावरण संरक्षण, वनो और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, व्यक्तियों और संपति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने संबंधित मामलो के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिनियम की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। यह विशिष्ट निकाय, पर्यावरण संबंधी विवादो का शीघ्र निपटारा करेगा। [8]

25 अप्रैल 2014 को एन.जी.टी ने कहा कि यमुना नदी पर प्रस्तावित मनोरंजक सुविधाओं के कारण यमुना का प्रदूषण बढ़ रहा। अतः दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की 52 किलोमीटर लंबी दूरी को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की। आयोग ने कहां मार्च 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग के तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम (श्री श्री रविशंकर द्वारा आयोजित) से यमुना प्रदुषित हुई है जिसकी सफाई के लिए 42 करोड़ रूपए खर्च आयेगा, सफाई का दिशा निर्देश दिया है। [9]

Scanned with CamScanner

जा सकता है। मानसून में डायरिया होने का मुख्य कारण भूमिगत जल में गंदगी, मल का मिलना है। स्वच्छ भारत मिशन का अगर ईमानदारी से पालन किया जाये तो बहुत सारी संक्रमित बीमारियों से बच सकते हैं एवं पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास

पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाता है। 25 जुलाई 2005 में धार्मिक अनुष्ठानों त्यौहारों, शादियों और संबंधित मौको पर ध्वनि प्रदुषण नियंत्रण की हिदायत दी हैं। दीपावली के समय फटाके फोड़ने के लिए समय का नियंत्रण (केवल दो घंटे– रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक) किया गया है। विभिन्न त्यौहारों में प्लास्टर आफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर निगम द्वारा पौधे लगाये जाते हैं एवं बांटे जाते हैं ताकि सर्वत्र हरयाली रहे।

सुझाव

पर्यावरण संरक्षण वास्तव में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल निर्माण कार्य रोकने, पलारी जलाने,कचरा जलाने पर पाबंदी करने पुरानी गाड़ियों को जब्त करने से प्रदूषण खत्म नही होने वाला है। विकास के पूरे मॉडल को बदलना जरुरी है। राजनीतिक दलों को पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान दे कर काम को चालू करना चाहिए। आम जनता और सरकार मिल कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करे तो हम अनेक समस्या से बच सकते है अतः निम्न प्रयास करना चाहिए–

1. पेड़ों को अधिक से अधिक लगायें इसे जन आंदोलन का रुप देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शशांक द्विवेदी/ आखिर कहां तक जायेगा प्रदूषण/ विज्ञान प्रगति/ जून 2018/ पृष्ठ 18
2. शशांक द्विवेदी/ आखिर कहां तक जायेगा प्रदूषण विज्ञान प्रगति/ जून 2018/ पृष्ठ 17
3. दैनिक भास्कर/विश्व पर्यावरण दिवस/जून 2018
4. विज्ञान प्रगति/ जून 2018/ पृष्ठ 19
5. विज्ञान प्रगति /पृ.19
6. दैनिक भास्कर 20–07–2018
7. दैनिक भास्कर 27–9–2018
8. विकिपीडिया/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010
9. www.greentribunal.gov.in
10. Isha. Sadhguru.org/rally-for-rivers/

Scanned with CamScanner